

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-158/2019

1. अयोध्या राम
2. तैमुल बीबी
3. ललिता देवी

.....याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, पलामू
3. अनुमण्डल अधिकारी, मेदिनीनगर, सदर, पलामू
4. प्रखण्ड विकास अधिकारी, नोआ बाजार, पलामू

..... विरोधी पक्षगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए : सुश्री नाजिया रशीद, अधिवक्ता।

विरोधी पार्टियों के लिए : श्री अभिजीत कुमार, एस०सी०-IV के ए०सी०

आदेश संख्या 03

दिनांक 27.09.2019

वर्तमान सी०एम०पी० को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2018 के डब्ल्यू०पी० (सी०) सं०-2520/2017 में पारित आदेश के संशोधन की मांग करते हुए दायर किया गया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता सं० 1 के पी०डी०एस० लाइसेंस नं० 9/2008 के अलावा, याचिकाकर्ता सं० 2 के लाइसेंस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाइसेंस सं० 3/2011 'बेहना स्वयं सहायता समुह, इटको' के सदस्य होने के कारण और याचिकाकर्ता सं० 3, लक्ष्मी विकास संघ का सदस्य होने के कारण, जिसके पास पी०डी०एस० लाइसेंस सं० 3/2010 है, रद्द कर दिया गया। इस प्रकार, डब्ल्यू०पी० (सी०) सं०-2520/2017 में पारित दिनांक 03.12.2018 के आदेश के पैरा 1 में याचिकाकर्ता सं० 2 और 3 के पी०डी०एस० लाइसेंस भी जोड़े जा सकते हैं।

डब्ल्यू०पी० (सी०) सं०-2520/2017 की रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रिट याचिका की कंडिका 1 (क) में की गई प्रार्थना केवल याचिकाकर्ता संख्या 1 तक ही सीमित थी।

इसलिए, इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू०पी० (सी०) सं०-2520/2017 में पारित दिनांक 03.12.2018 के आदेश का संशोधन, वर्तमान सी०एम०पी० के माध्यम से याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रार्थना के अनुसार विचार योग्य नहीं है।

वर्तमान सी०एम०पी० को, तदनुसार, खारिज कर दिया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया०)